26th September, 2020

NEWS JUICE हिंदी में

Translation of The Hindu & The Indian Express

मुख्य खबरें

1. भारत और पाकिस्तान सार्क में व्यापार शुल्क, **CICA** मुलाक़ात

2. हार्ले-डेविडसन भारत में बिक्री और विनिर्माण कार्यों को बंद करने के लिए तत्पर

3. आवश्यक वस्तुओं को फिर से परिभाषित करना

4. कोविद -19 के लिए नाक के दवाई कैसे काम करती है?

5. एसपी ग्रुप का टाटा ग्रुप से बाहर निकलना

News Juice कैसे तैयार किया जाता है?

BY PREPMATE

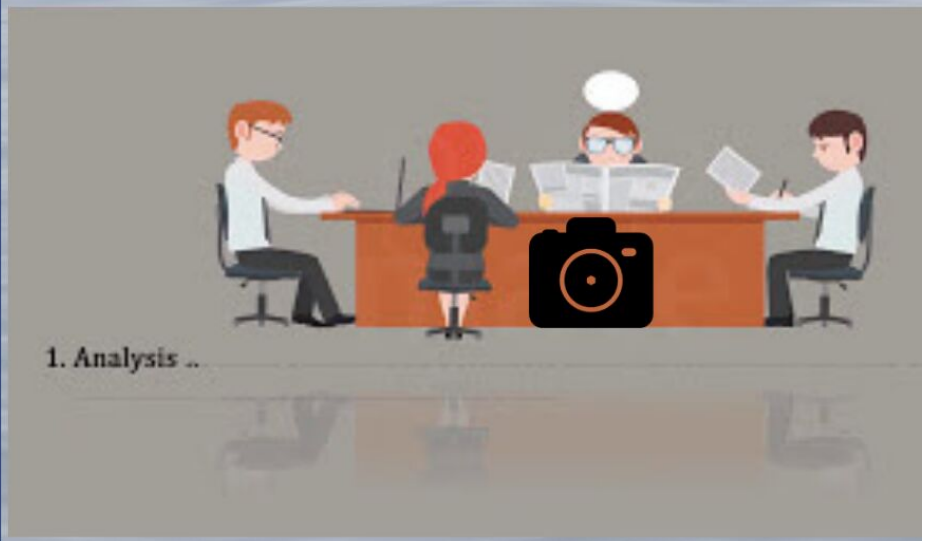

1. भारत और पाकिस्तान सार्क में व्यापार शुल्क, CICA मुलाक़ात

Relevant for GS Prelims & Mains Paper II; IOBR

भारत और पाकिस्तान ने आतंकवाद और जम्मू-कश्मीर में विदेश मंत्री के 8-देशों के दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (SAARC) की ऑनलाइन बैठकों और एशिया (CICA) में सहभागिता और विश्वास-निर्माण उपायों पर 27-राष्ट्र सम्मेलन को पार किया। हालांकि, अतीत में समान अवसरों के विपरीत, गुरुवार को वीडियो-कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित कार्यक्रमों के दौरान कोई पक्ष सामने नहीं आया।
दक्षिण एशियाई बैठक में बोलते हुए, विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने सभी सार्क सदस्यों से "सामूहिक रूप से आतंकवाद के संकट को हराने के लिए संकल्प लिया, जिसमें आतंक और संघर्ष के वातावरण का पोषण, समर्थन और प्रोत्साहित करने वाली ताकतों सहित, जिसने सार्क के उद्देश्य को पूरा करने के लिए दक्षिण एशिया में सामूहिक सहयोग और समृद्धि के लिए अपनी पूरी क्षमता का एहसास कराया।

जम्मू और कश्मीर के लिए संदर्भ

अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका के विदेश मंत्रियों के साथ बैठक में भाग लेने वाले पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने "लंबे समय से चले आ रहे विवादों के समाधान" पर विस्तृत बयान देने के लिए सार्क मंच का इस्तेमाल किया। जम्मू और कश्मीर और नई दिल्ली के 2019 के कदम को वापस लेने के लिए अनुच्छेद 370 को हटा दिया गया।

अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका के विदेश मंत्रियों के साथ बैठक में भाग लेने वाले पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने "लंबे समय से चले आ रहे विवादों के समाधान" पर विस्तृत बयान देने के लिए सार्क मंच का इस्तेमाल किया। जम्मू और कश्मीर और नई दिल्ली के 2019 के कदम को वापस लेने के लिए अनुच्छेद 370 को हटा दिया गया।

रिपोर्ट में कहा गया है कि श्री कुरैशी ने "लंबे समय से चल रहे विवादों से पीड़ित लोगों के व्यवस्थित मानवाधिकारों के उल्लंघन" का जिक्र किया।

इसी तरह का बयान CICA के विशेष मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में किया गया था, जो एशियाई देशों को रूस और मध्य एशिया से खाड़ी और दक्षिण-पूर्व एशिया में लाता है।

भारत ने जवाब देने के अधिकार में श्री कुरैशी को फटकार लगाई, एमईए ने कहा। भारत ने कहा कि हम पाकिस्तान को सलाह देते हैं कि वह अपने प्रायोजन को खत्म करे और भारत के खिलाफ आतंकवाद को समर्थन प्रदान करे।

Source: The Hindu

2. हार्ले-डेविडसन भारत में बिक्री और विनिर्माण कार्यों को बंद करने के लिए तत्पर

Relevant for GS Prelims & Mains Paper III; Economics

हार्ले-डेविडसन इंक ने गुरुवार को कहा कि यह भारत में अपनी बिक्री और विनिर्माण कार्यों को बंद कर देगा, एक दशक के असफल प्रयासों के बाद दुनिया के सबसे बड़े मोटरसाइकिल बाजार को प्रभावी ढंग से छोड़ने के लिए।

हार्ले ने देश में डीलरशिप को सस्ता करने के लिए हाल के महीनों को स्थानांतरित करने में खर्च किया था, और घोषणा ने एक महीने पहले भारतीय मीडिया में अटकलों का पालन किया था जो अधिकारियों ने खेले थे।

इस कदम में 75 मिलियन डॉलर की लागत, कुछ 70 अतिरेक और इसके बावल संयंत्र को बंद करने के साथ-साथ बाजार से लगभग 17 मिलियन बाइक और स्कूटर की बिक्री से एक साल दूर चलना शामिल है। यह नई दिल्ली के दक्षिण में गुड़गांव में केवल एक स्केल-डाउन बिक्री कार्यालय बनाए रखेगा।

प्रभाव क्या है?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करने की रणनीति के लिए प्रस्थान भी नवीनतम झटका है जो भारत में एक विशाल घरेलू उपभोक्ता बाजार के अधिक फल देगा।

भारत अभी भी कई विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में सस्ता और गरीब है, जिसके साथ यह निवेश के लिए प्रतिस्पर्धा करता है, अन्य ऑटो उद्योग के खिलाड़ियों के लिए एक अमानवीय बाजार साबित हुआ है।

Source: The Indian Express

3. आवश्यक वस्तुओं को फिर से परिभाषित करना: इसकी आवश्यकता क्यों थी, और यह किस पर प्रभाव डालेगा

Relevant for GS Prelims & Mains Paper III; Economics

मंगलवार को, राज्य सभा ने आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक, 2020 पारित किया, जिसका उद्देश्य अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज और आलू जैसी वस्तुओं को निष्क्रिय करना है। विधेयक पिछले सप्ताह लोकसभा में पेश और पारित किया गया था। यह अध्यादेश की जगह लेता है कि सरकार ने 5 जून को कृषि क्षेत्र पर दो अन्य अध्यादेशों के साथ प्रख्यापित किया था। पंजाब और हरियाणा में किसानों के विरोध प्रदर्शनों को देखने वाले दो अन्य अध्यादेशों (जैसे विधेयकों के रूप में भी पारित) के साथ, इस विधेयक के प्रावधानों के बारे में भी चिंता की गई है।

विधेयक किस बारे में है?

यह एक चार-पृष्ठ विधेयक है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में संशोधन करता है, धारा 3 में एक नया अंशदान (1 ए) शुरू करके। संशोधन के बाद, कुछ खाद्य पदार्थों की आपूर्ति - जिसमें अनाज, दालें, तिलहन, खाद्य तेल, आलू शामिल हैं - को केवल असाधारण परिस्थितियों में ही विनियमित किया जा सकता है, जिसमें एक असाधारण मूल्य वृद्धि, युद्ध, अकाल और एक गंभीर प्रकृति की प्राकृतिक आपदा शामिल है। वास्तव में, संशोधन इन वस्तुओं को धारा 3 (1) के दायरे से बाहर ले जाता है, जो केंद्र सरकार को "आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, आपूर्ति, वितरण, आदि" को नियंत्रित करने की शक्तियां देता है।

इससे पहले, इन वस्तुओं का उल्लेख धारा 3 (1) के तहत नहीं किया गया था और अनुभाग को लागू करने के कारणों को निर्दिष्ट नहीं किया गया था। संशोधनों में कहा गया है कि "स्टॉक सीमा को विनियमित करने के लिए ऐसा आदेश किसी भी कृषि उपज के प्रोसेसर या वैल्यू चेन प्रतिभागी पर लागू नहीं होगा, अगर ऐसे व्यक्ति की स्टॉक सीमा प्रसंस्करण की स्थापित क्षमता की समग्र सीमा से अधिक नहीं है, या एक निर्यातक के मामले में निर्यात की मांग... "

आवश्यक वस्तु को कैसे परिभाषित किया जाता है?
आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में आवश्यक वस्तुओं की कोई विशेष परिभाषा नहीं है। धारा 2 (ए) में कहा गया है कि "आवश्यक वस्तु" का अर्थ अधिनियम की अनुसूची में निर्दिष्ट वस्तु है।

अधिनियम केंद्र सरकार को अनुसूची में एक वस्तु को जोड़ने या हटाने की शक्तियां देता है। केंद्र, यदि यह संतुष्ट है कि सार्वजनिक हित में ऐसा करना आवश्यक है, तो राज्य सरकारों के परामर्श से किसी वस्तु को आवश्यक रूप से अधिसूचित किया जा सकता है।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अनुसार, जो अधिनियम को लागू करता है, वर्तमान में अनुसूची में सात वस्तुएं शामिल हैं - दवाएं; उर्वरक, चाहे अकार्बनिक, जैविक या मिश्रित; खाद्य तेलों सहित खाद्य पदार्थ; कपास से पूरी तरह से बना यार्न; पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद; कच्चे जूट और जूट वस्त्र; खाद्य-फसलों के बीज और फल और सब्जियों के बीज, पशुओं के चारे के बीज, जूट के बीज, कपास के बीज।

किसी वस्तु को आवश्यक घोषित करके, सरकार उस वस्तु के उत्पादन, आपूर्ति और वितरण को नियंत्रित कर सकती है और स्टॉक सीमा लागू कर सकती है।

सरकार किन परिस्थितियों में स्टॉक लिमिट लगा सकती है?
जबकि 1955 अधिनियम ने स्टॉक सीमा लगाने के लिए एक स्पष्ट ढांचा प्रदान नहीं किया था, संशोधित अधिनियम मूल्य ट्रिगर के लिए प्रदान करता है। जबकि 1955 अधिनियम ने स्टॉक सीमा लगाने के लिए एक स्पष्ट ढांचा प्रदान नहीं किया था, संशोधित अधिनियम मूल्य ट्रिगर के लिए प्रदान करता है।

हालांकि, स्टॉक सीमा लगाने पर कोई भी कार्रवाई मूल्य ट्रिगर पर आधारित होगी।

इस प्रकार, बागवानी उपज के मामले में, तुरंत 12 महीने से पहले या पिछले पांच वर्षों के औसत खुदरा मूल्य से कम, जो भी कम हो, स्टॉक सीमा को लागू करने के लिए ट्रिगर होगा।

गैर-नाशपाती कृषि खाद्य पदार्थों के लिए, मूल्य ट्रिगर तुरंत 12 महीने या पिछले पांच वर्षों के औसत खुदरा मूल्य से कम, जो भी कम हो, कमोडिटी के खुदरा मूल्य में 50% की वृद्धि होगी।

हालांकि, स्टॉक-होल्डिंग सीमा से छूट किसी भी कृषि उपज के प्रोसेसर और मूल्य श्रृंखला प्रतिभागियों, और सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित आदेशों को प्रदान की जाएगी।

"मूल्य ट्रिगर स्टॉक सीमा के तहत आदेशों को लागू करने से जुड़ी पिछली अनिश्चितताओं को भी कम करेगा। यह अब अधिक पारदर्शी होगा और बेहतर प्रशासन में मदद करेगा," उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के एक सूत्र ने कहा।

"पिछले 10 वर्षों में ईसी अधिनियम के लंबे समय तक लागू होने की अवधि देखी गई है। एक बार लगाए जाने के बाद, वे लंबे समय तक थे - 2006 से 2017 तक दाल, 2008 से 2014 तक चावल, 2008 से 2018 तक खाद्य तिलहन। चुनाव आयोग अधिनियम में संशोधन स्टॉक सीमाओं को लागू करने और इसे और अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की प्रक्रिया के लिए मानदंड को परिभाषित करके इस अनिश्चितता को दूर करना चाहते हैं," स्रोत ने कहा।

इसकी आवश्यकता क्यों महसूस की गई?

1955 अधिनियम एक ऐसे समय में कानून बनाया गया था जब देश खाद्यान्न उत्पादन के लगातार निम्न स्तर के कारण खाद्य पदार्थों की कमी का सामना कर रहा था। देश आबादी को खिलाने के लिए आयात और सहायता (जैसे गेहूं आयात पीएल -480 के तहत अमेरिका का गठन) पर निर्भर था। खाद्य पदार्थों की जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकने के लिए 1955 में आवश्यक वस्तु अधिनियम बनाया गया था।

लेकिन अब स्थिति बदल गई है। उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए एक नोट से पता चलता है कि गेहूं का उत्पादन 10 गुना (1955-56 में 10 मिलियन टन से कम हो गया है) 2018-19 में 100 मिलियन टन से अधिक हो गया है। जबकि इसी अवधि के दौरान चावल का उत्पादन चार गुना (लगभग 25 मिलियन टन से 110 मिलियन टन) से अधिक हो गया है। दालों का उत्पादन 2.5 गुना बढ़कर 10 मिलियन टन से 25 मिलियन टन हो गया है।

वास्तव में, भारत अब कई कृषि उत्पादों का निर्यातक बन गया है।

संशोधनों का क्या होगा असर?

मुख्य परिवर्तन परमिट और मंडियों द्वारा लगाए गए सीमाओं से कृषि बाजारों को मुक्त करना चाहते हैं जो मूल रूप से बिखराव के युग के लिए डिज़ाइन किए गए थे। इस कदम से अनाज, दाल, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज और आलू जैसी आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटाई गई वस्तुओं की मूल्य श्रृंखला में निजी निवेश को आकर्षित करने की उम्मीद है।

जबकि अधिनियम का उद्देश्य मूल रूप से अवैध व्यापार प्रथाओं जैसे जमाखोरी की जाँच करके उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना था, अब यह सामान्य रूप से कृषि क्षेत्र में और विशेष रूप से कटाई के बाद की गतिविधियों में निवेश के लिए एक बाधा बन गया है। निजी क्षेत्र ने अब तक खराब वस्तुओं के लिए कोल्ड चेन और भंडारण सुविधाओं में निवेश के बारे में संकोच किया था क्योंकि इनमें से अधिकांश वस्तुएं ईसी अधिनियम के दायरे में थीं, और अचानक स्टॉक सीमा को आकर्षित कर सकती थीं। इस तरह की चिंताओं को दूर करने के लिए संशोधन चाहता है।

इसका विरोध क्यों किया जा रहा है?
यह उन तीन अध्यादेशों / विधेयकों में से एक था, जिन्होंने देश के कुछ हिस्सों में किसानों के विरोध को देखा है। विपक्ष का कहना है कि संशोधन से किसानों और उपभोक्ताओं को नुकसान होगा और इससे केवल जमाखोरों को फायदा होगा। वे कहते हैं कि बिल में लागू मूल्य ट्रिगर अवास्तविक हैं - इतना अधिक है कि उन्हें शायद ही कभी लागू किया जाएगा।

Source: The Indian Express

4. कोविद -19 के लिए नाक के दवाई कैसे काम करती है: उपयोगिता और सरोकार

Relevant for GS Prelims & Mains Paper III; Science & Technology

भारत बायोटेक ने बुधवार को घोषणा की कि यह एकल-खुराक इंट्रानैसल वैक्सीन की एक अरब खुराक तक का निर्माण करेगा। यह इस मार्ग के माध्यम से प्रशासित देश का पहला टीका प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

इंट्रानैसल वैक्सीन क्या है?
टीकों को विभिन्न मार्गों के माध्यम से वितरित किया जाता है, जिसमें मांसपेशियों (इंट्रामस्क्युलर) या त्वचा और मांसपेशियों (चमड़े के नीचे) के बीच के ऊतकों में सबसे सामान्य इंजेक्शन लगाने योग्य शॉट्स दिए जाते हैं। प्रसव के अन्य मार्गों, विशेष रूप से शिशुओं के लिए कुछ टीकों में, इंजेक्शन के बजाय मौखिक रूप से तरल घोल को शामिल करना शामिल है। इंट्रानासल मार्ग में, वैक्सीन को नथुने में फंसाया जाता है।
कोविद -19 के लिए इस तरह की दवाई का क्या महत्व है?

वाशिंगटन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन द्वारा सेंट लुइस में विकसित और भारत बायोटेक को लाइसेंस प्राप्त एकल-शॉट इंट्रानैसल कोविद -19 वैक्सीन का लक्ष्य बड़े पैमाने पर टीकाकरण के साथ संभावित कठिनाइयों को दूर करना और सुइयों और सिरिंजों की आवश्यकता को पूरा करके लागत को कम करना है।

विशेषज्ञों के अनुसार, वैक्सीन का टीका लगाने के लिए विभिन्न प्रशिक्षित कर्मियों पर निर्भरता में कटौती करने की उम्मीद है।

"आइए, यह न भूलें कि महामारी के पैमाने के साथ, वास्तव में केवल वैक्सीन शिपिंग है, यह उपलब्ध है और फिर लोगों को बांह में इंजेक्शन देने के लिए प्रशिक्षित किया जाना इतना आसान नहीं है। इसलिए, इंट्रा नास वैक्सीन के साथ एक आकर्षण यह है कि इसका उपयोग करना बहुत सरल है - आप इसे अपनी नाक में डाल लेते हैं - और यह कुछ ऐसा है जो महामारी और प्रकोप में स्व-प्रशासित हो सकता है," हिलमैन लैबोरेटरीज के पूर्व सीईओ डॉ. दविंदर गिल ने कहा।

वैक्सीन वैज्ञानिक डॉ. गगनदीप कांग ने कहा, "यह एक आसान-सा वैक्सीन है।" "यह एक म्यूकोसल सतह में जा रहा है, प्रतिबंधित होने की संभावना है (और वहाँ) कम सुरक्षा घटनाओं की संभावना है। यह इन्फ्लूएंजा के टीकों के संयोजन में दिया जा सकता है," उन्होंने कहा।

वायरोलॉजिस्ट और वेलकम ट्रस्ट डीबीटी इंडिया एलायंस के सीईओ डॉ. शाहिद जमील ने कहा कि एक इंट्रानैसल वैक्सीन एक अलग तरह की प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया बनाने में भी मदद कर सकता है।

"इंट्रानैसल और इंट्रामस्क्युलर दोनों टीके रक्त में प्रतिक्रिया उत्पन्न करते हैं ... लेकिन, नाक या मुंह के माध्यम से प्रशासित टीके भी म्यूकोसल ऊतकों में पाए जाने वाले प्रतिरक्षा कोशिकाओं के एक और सेट में टैप करेंगे। यहां रहने वाली बी कोशिकाएं एक अन्य प्रकार का एंटीबॉडी बना सकती हैं, जिसे आईजीए कहा जाता है, जो आंत और वायुमार्ग के रोगजनकों को नष्ट करने में बहुत प्रभावी है। इस ऊतक में टी कोशिकाएं एक मेमोरी बना सकती हैं और उन स्थानों पर गश्त कर सकती हैं, जहां वे पहले रोगजनकों का सामना कर चुके हैं, "उन्होंने कहा।

क्या इस तरह के टीके के साथ संभावित समस्याएं हैं?

कई लोग अपने कोविद -19 वैक्सीन के प्रशासन के लिए इंट्रानासल मार्ग पर विचार नहीं कर रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) द्वारा सूचीबद्ध 187 कोविद -19 वैक्सीन उम्मीदवारों में से, केवल पांच विशेष रूप से सूचीबद्ध हैं, जो विशेष रूप से प्रसव के इंट्रानेसल मार्ग की खोज के रूप में सूचीबद्ध हैं।

ऐसा इसलिए है क्योंकि अभी तक डिलीवरी के इस मार्ग की प्रभावशीलता को कम करने के लिए बहुत कम सबूत हैं और, कुछ फ्लू टीकों को बचाने के लिए, टीकों को वितरित करने के प्रयास विशेषज्ञों के अनुसार सफल नहीं हुए हैं।

"सैद्धांतिक फायदे के बावजूद, टीकाकरण के लिए इंट्रानैसल दृष्टिकोण काफी हद तक अप्रमाणित है। हालांकि इस अवधारणा का जानवरों में काफी व्यापक रूप से परीक्षण किया गया है, क्या यह सच है कि मनुष्यों में यह अभी भी काफी हद तक अप्राप्त है और इसलिए यहां नैदानिक परीक्षणों को निश्चित रूप से करीब से देखा जाना होगा," डॉ गिल ने कहा। "फ्लू के टीके के लिए बचाएं, इस तरह के टीके का उपयोग करने के लिए वास्तव में एक मिसाल नहीं है।"

डॉ. कंग ने कहा, "खसरे के टीके का परीक्षण किया गया था जो गैर-हीनता मानदंडों को पूरा नहीं करता था।" "नाक फ्लू के टीके जो लाइव-अटेच किए गए टीके हैं, उन्होंने अच्छी तरह से नहीं किया है। हम नहीं जानते कि क्या यह इस तथ्य के साथ एक समस्या है कि वे फ्लू के टीके हैं, या क्या यह एक नाक टीका होने

के साथ एक समस्या है।" उसने कहा कि एक स्प्रे बनाम एक इंजेक्शन के साथ आप किस खुराक से संबंधित अनिश्चितता है।

डॉ. जमील ने कहा कि केवल बहुत छोटे खंड - आमतौर पर लगभग 0.1 मिलीलीटर - इंट्रानासल मार्ग के माध्यम से प्रत्येक नथुने में प्रशासित किए जा सकते हैं। "टीके के एंटीजन उच्च एकाग्रता में उत्पादित किए जाने चाहिए। एकल या एकाधिक उपयोग के लिए उचित वितरण वाहनों को विकसित किया जाना है और ये सबसे महत्वपूर्ण चुनौती पेश करते हैं, "उन्होंने कहा।

Source: The Indian Express

5. एसपी ग्रुप का टाटा ग्रुप से बाहर निकलना: कौन अपनी हिस्सेदारी खरीद सकता है, और कैसे?

Relevant for GS Prelims & Mains Paper III; Economics

84 वर्षों के संघ के बाद, शापूरजी पल्लोनजी मिस्त्री (एसपी) समूह ने टाटा संस से बाहर निकलने की पेशकश की है क्योंकि टाटा के साथ मुकदमेबाजी ने एसपी समूह की व्यापार विस्तार योजनाओं को प्रभावित किया है, जिस पर 30,000 करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज बोझ है।

टाटा समूह की सूचीबद्ध संस्थाओं में एसपी समूह की हिस्सेदारी का बाजार मूल्य 148,000 करोड़ रुपये से अधिक होने का अनुमान है, जो सभी सूचीबद्ध समूह फर्मों के बाजार पूंजीकरण द्वारा किया जाता है। यह देखना बाकी है कि टाटा समूह ने एसपी समूह की हिस्सेदारी हासिल करने के लिए नकदी कैसे जुटाई।

सभी के बारे में नवीनतम मामला क्या है?

इस महीने की शुरुआत में, टाटा संस ने एसपी समूह की कंपनियों को टाटा संस में अपनी हिस्सेदारी की सुरक्षा के खिलाफ पूंजी जुटाने से रोकने के लिए उच्चतम न्यायालय का रुख किया। टाटा ने तर्क दिया कि एसोसिएशन (एओए) के लेख यह बताते हैं कि शेयर उधारदाताओं या अन्य पक्षों सहित हाथों को बदल नहीं सकते हैं, और पहले इनकार का अधिकार टाटा संस के साथ है। एसपी समूह टाटा संस के शेयरों को गिरवी रखकर रियल एस्टेट विस्तार के लिए धन जुटाने की योजना बना रहा था। टाटा समूह के चेयरमैन के रूप में चार साल पहले हटाए जाने के बाद से टाटा और एसपी ग्रुप कई कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं।

मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में, एसपी ग्रुप ने कहा "जीविका और अर्थव्यवस्था पर इस निरंतर मुकदमेबाजी के संभावित प्रभाव के कारण टाटा समूह से अलगाव आवश्यक है"। टाटा समूह एसपी समूह द्वारा आयोजित टाटा संस के शेयरों को खरीदने के लिए खुला है ताकि बाद के धन उगाहने के प्रयासों में मदद की जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने एसपी ग्रुप को टाटा संस के शेयर ट्रांसफर या गिरवी रखने से रोक दिया।

एसपी समूह ने टाटा संस में हिस्सेदारी कब हासिल की?

साइरस के दादाजी शापूरजी पल्लोनजी मिस्त्री ने 1936 में टाटा संस में 12.5% हिस्सेदारी खरीद ली थी, जो कि एफ ई दिनशॉ के वारिस थे, जो एक करीबी दोस्त और टाटा के सहयोगी थे। 1996 में राइट्स इश्यू के

बाद यह हिस्सेदारी 18.5% हो गई। टाटा और मिस्त्री परिवारों ने सौहार्दपूर्ण संबंधों को बनाए रखा है, जो वर्षों से वैवाहिक संबंधों तक बढ़ा है: रतन टाटा के सौतेले भाई नोएल टाटा की शादी साइरस की बहन आलू से हुई है।

Tata Sons में SP Group का कितना योगदान है?

टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी टाटा संस में इसकी 18.37% हिस्सेदारी है, जबकि 66% की बहुमत रतन टाटा के नेतृत्व वाले टाटा ट्रस्ट्स द्वारा नियंत्रित है। जबकि टाटा समूह की 17 सूचीबद्ध संस्थाओं का कुल बाजार पूंजीकरण 12.96 लाख करोड़ रुपये है, टाटा समूह की सूचीबद्ध कंपनियों में एसपी समूह की हिस्सेदारी का मूल्यांकन लगभग 1.48 लाख करोड़ रुपये है। चूंकि टाटा संस, टाटा समूह की असूचीबद्ध संस्थाओं की होल्डिंग कंपनी भी है, इसलिए एसपी समूह के मूल्यांकन में भी हिस्सेदारी होगी; इसके लिए अलग से काम करना होगा।

एसपी ग्रुप की हिस्सेदारी कौन खरीद सकता है?

जबकि एसपी समूह ने कहा है कि टाटा समूह से उसका अलगाव आवश्यक है, बाद वाले ने कहा कि वह पूर्व की हिस्सेदारी खरीदने के लिए तैयार है। यह विश्वसनीय रूप से सीखा गया है कि टाटा संस के लेख में कहा गया है कि यदि टाटा संस का कोई शेयरधारक अपना शेयर बेचना चाहता है, तो उसे पहले टाटा संस को प्रस्ताव देना होगा। टाटा संस इसके बाद उचित बाजार मूल्य तय करेगी और इसे पेश करेगी।

टाटा समूह के लिए यह हिस्सेदारी खरीदना कितना आसान होगा?

निवेश बैंकरों और वित्त विशेषज्ञों का कहना है कि एसपी समूह के शेयरों को वापस खरीदने के लिए टाटा समूह की पेशकश में जटिलताओं की विभिन्न परतें शामिल हैं। पहला मुद्दा जो क्रॉप करेगा, वह यह होगा कि दोनों पक्ष इस पर सहमत होंगे। एक और मुद्दा यह है कि अगले एक महीने में, टाटा समूह को यह दिखाने के लिए एक वित्तपोषण योजना तैयार करनी होगी कि वह उस अधिग्रहण को कैसे निधि देगा और उस उधार के लिए ग्रहणाधिकार के रूप में क्या डालेगा।

एक निवेश बैंकर ने कहा, "टीसीएस को छोड़कर, टाटा समूह की कई कंपनियां बड़े आकार में नहीं हैं - विशेष रूप से उनके स्टील और ऑटो और बिजली कारोबार में भारी कर्ज है।"

दूसरी ओर, अगर टाटा समूह इन शेयरों को खरीदने के लिए कुछ वैश्विक निवेशकों को लाने की योजना बना रहा है, तो बाजार सहभागियों का कहना है कि ऐसे निवेशक जानना चाहेंगे कि टाटा संस 7-10 साल बाद उन्हें कैसे बाहर निकालेगी क्योंकि टाटा संस एक असूचीबद्ध इकाई है।

साइरस मिस्त्री को टाटा संस के अध्यक्ष के रूप में कब हटाया गया था?

24 अक्टूबर, 2016 को, टाटा संस के बोर्ड ने साइरस मिस्त्री को अपने अध्यक्ष के रूप में हटा दिया, लगभग चार साल बाद उन्होंने पदभार संभाला था। मिस्त्री, जो बोर्ड में निदेशक थे, को 2011 में समूह का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था और फिर 2012 में अध्यक्ष पद पर पदोन्नत किया गया था। मिस्त्री ने

व्यवसाय प्रथाओं में कई बदलावों को प्रभावित किया, जिसके कारण पूंजीगत व्यय में वृद्धि हुई लेकिन शेयरधारकों को रिटर्न कम हो गया। ब्रिटेन में टाटा स्टील के पोर्ट टैलबोट संयंत्र की प्रस्तावित बिक्री को

टाटा द्वारा विदेशों में अर्जित की गई सद्भावना को नुकसान पहुंचाने के रूप में देखा गया। जापान के डोकोमो समूह के साथ एक विवाद, एयर एशिया और टाटा मोटर्स में समस्याएं और कुछ अधिग्रहण ने रतन टाटा को परेशान किया।

Source: The Indian Express

PrepMate - Cengage UPSC Book Series

अभी ऑर्डर करने के लिए यहाँ क्लिक करें

श्रृंखला के बारे में

एक पुस्तक में एक विषय का पूरा पाठ्यक्रम विस्तार

अवधारणाओं को समझने के लिए प्रवाह संचित्र, मानचित्र और आरेखों का उपयोग

विस्तृत समाधान के साथ अभ्यास प्रश्न

पिछली प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्नों काअध्यायवार विस्तृत समाधान

मुख्य परीक्षा उत्तर लिखने के लिए एक पूर्ण और व्यावहारिक दृष्टिकोण

लेखकों द्वारा UPSC प्रमुख परीक्षा के उत्तर

पुस्तकों के साथ वीडियो का भंडार